FRs for 11 link project (2 under Himalayan component and 9 under Peninsular Component) have been completed by NWDA so far. The Government under its Common Minimum Programme envisages for a comprehensive assessment of the feasibility of linking of the rivers of the country.

(b) There are three link proposals under Peninsular component of National Perspective Plan (NPP) envisaging diversion of water from west flowing rivers to eastern direction:

1. Pamba-Achankovil-Vaippar link
2. Netravati-Hemavati link
3. Bedti-Varada link.

(c) No such proposal is under consideration of this Ministry.

Water Management Policy

†301. SHRI P.K. MAHESHWARI: Will the Minister of WATER RESORUCES be pleased to state:

(a) the details of measures taken by Government in view of constantly growing problem of potable water; and

(b) whether Government are contemplating to formulate any appropriate policy in respect of water management?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESORUCES (SHRI JAY PRAKASH NARAYAN YADAV): (a) and (d) Water being a State subject, water resoruces schemes including schemes for drinking water supply are planned, formulated and implemented by the State Government out of their own resources. However, to supplement the efforts of the State Government, the Government of India provides technical & financial assistance to the States under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply and Accelerated Urban Water Supply Programmes.

National Water Policy, 2002 provides first priority to the Drinking Water in the planning and operation of systems. Further, the Policy envisages that adequate safe drinking water facilities should be provided to the entire population both in urban and in rural areas and irrigation and

† Original notice of the Question was received in Hindi.

multipurpose project should invariably include a drinking water component, wherever there is no alternative source of drinking water.

RE. SOME POINTS ARISING OUT OF PUNJAB RIVER WATER BILL, 2004

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): सभापति जी, जो बात यहां जल संसाधन मंत्री ने रखी थी...

श्री सभापति: हाऊस को चलने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं सर, उसके बाद तो बिलकुल एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है पंजाब के अंदर और देखा जाए तो पूरे देश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। ... (**व्यवधान**)... एक ऐसा बिल पारित हो जाए पंजाब विधान सभा के द्वारा जिसमें लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए अब हमें जल संसाधन मंत्री नहीं, प्रधान मंत्री चाहिए। ... (**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): सभापति महोदय, इस पर बहस नहीं हो रही है। ... (**व्यवधान**)... महोदय ये आपकी परमीशन के बिना बोल रही हैं, इसलिए यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): This move affects the whole nation ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमें प्रधान मंत्री चाहिए और प्रधान मंत्री आकर इस सदन को बताएं। ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, यह तो कंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक सरकार ऐसा बिल पारित कर दे, जो उसके कॉन्फिडेंस में नहीं हो और गवर्नर उसको ऐसेंट भी दे दें, इसलिए यह मामला बहुत गंभीर रूप धारण कर चुका है। देखा जाए तो पंजाब में कंस्टीट्युशनल ब्रेकडाउन हुआ है, देश में संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। इसलिए आप प्रधान मंत्री को यहां बुलाइए ताकि प्रधान मंत्री सदन को आश्वस्त करें कि वे इसका क्या समाधान निकालने वाले हैं? ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, आपने इनको बोलने की परमीशन नहीं दी है। ... (**व्यवधान**)...

श्रीमती अम्बिका सोनी (पंजाब): कोई संकट नहीं खड़ा हुआ है। ... (**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, प्रधान मंत्री को बुलाइए, तभी इसका समाधान होगा। ...(**व्यवधान**)...